Starred Assembly Question No. *59 (14/14/40)

QUANTITY OF ROTTEN FOOD GRAIN

***59 (14/14/40) Rao Dan Singh (Mahendragarh).: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-**

a) The total quantity of food grain rotten/damaged in the warehouses of Government in State during the last 7 years together with the reasons therefore along with the total price of above said rotten/damaged food grain; and

b) Whether the said food grain have been rotten due to negligence of departmental officers; if so, the action taken by the Government against such officers so far?

Answer: Deputy Chief Minister, Minister of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana

Sir,

a) In the last 7 years during crop years 2016-17 to 2022-23, 4073 MT and 74735 MT wheat stock stored in godowns and open plinth respectively has been damaged. The total cost of this stock is approximately Rs. 106 Crore as per the Minimum Support Price (MSP) of the relevant crop year.

b) In order to ascertain the reasons for damage of wheat stock in the State during crop year 2018-19, 2019-20 and 2020-21, a committee has been constituted under the chairmanship of Administrative Secretaries-District In charge vide Govt. order No. 05/5/2021-1MC, dated 14.11.2022/25.11.2022.

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या *59 (14/14/40)

खराब हुए खाद्यान्न की मात्रा

*59 (14/14/40) श्री राव दान सिंह(महेन्द्रगढ): क्या उप मुख्यमंत्री महोदय कृपया बताने का कष्ट करेंगेः-

क) पिछले 7 वर्षों में सरकारी गोदामों में खराब हुए खाद्यान्नों की मात्रा तथा खराब होने के कारण, खराब हुए खाद्यान्नों की कुल कीमत तथा

ख) ख)यदि उक्त खाद्यान विभाग के अधिकारियों की लापहरवाही से खराब हुआ है, यदि हां, तो जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ की गई कारवाई ?

उत्तर-(क) पिछले 7 वर्षो में खरीद वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान गोदामों/खुले में भण्डारित क्रमशः 4073 एम.टी. तथा 74735 एम.टी. खराब हुआ है। जिसकी कुल कीमत सम्बन्धित खरीद वर्ष के न्यूनतम खरीद मूल्य अनुसार लगभग 106 करोड रूपये बनती है।

उत्तर-(ख) वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के राज्य में खराब हुए गेहूं के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के आदेश न05/5/2021-1एम.सी. दिनांक 14.11.2022/25.11.2022 द्वारा प्रशासकीय सचिवों, जिला प्रभारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करते हुए जांच करवाई जा रही है।

------::------